ई-संदेश

2 अक्टूबर, 2025 | अंक 173

सात दिन – सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारत में नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था के पर्व पर कन्या पूजन करते हुए।

- सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा की बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री
- विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने में गांवों की सबसे अहम भूमिका : मुख्यमंत्री
- अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
- प्रदेश की 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म तथा नैतिक दायित्व : मुख्यमंत्री
- भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत उतना मजबूत और लोक कल्याण एवं वैश्विक कल्याण उतना ही सशक्त होगा : मुख्यमंत्री
- आदिवासी समाज हमारी गौरवशाली ऋषि परम्परा का वाहक: मुख्यमंत्री
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विजयदशमी के अवसर पर जन-जन की आस्था से जुड़ते हुए
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा की बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 सितम्बर, 2025 को लखनऊ में यहां छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 03 लाख 96 हजार 602 छात्र-छात्राओं को 89.96 करोड़ रुपये की धनराशि छात्र-छात्राओं को प्रदान की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा वह माध्यम है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक हो सकता है। जरुरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था से जोड़कर उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इनकी प्रतिभा का लाभ विगत 11 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश व दुनिया को प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि आज 04 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। यह कार्यक्रम छात्र-छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वंचित वर्गो एवं कमजोर आय वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कराते हुए तथा उनकी शैक्षिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर उन्हें समर्थ और सशक्त बनाने हेतु कक्षा 09 से 12 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 04 लाख छात्र-छात्राओं को लगभग 90 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करते हुए लाभान्वित कराया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के कक्षा 09 से 12 तक के 01 लाख 12 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रथम चरण में 20.23 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित कराया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पहले चरण में कक्षा 09 से 12 तक के अन्य पिछड़ा वर्ग के 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 62.13 करोड़ रुपये की धनराशि से लाभान्वित कराया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 09 से 12 के अल्पसंख्यक वर्ग के 25,073 छात्र-छात्राओं को 7.60 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रथम चरण में लाभान्वित कराया जा रहा है।प्रदेश के कुछ जनपदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति से जुड़े छात्र-छात्राओं को कुछ संस्थानों द्वारा डाटा अपलोड न करने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकी थी। प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी लगभग 05 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके। 05 वर्ष से 14 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रुप से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बेटियों की स्नातक तक की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र-छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने तथा स्कूल ड्रॉप आउट को कम करते हुए शिक्षा को सर्वसमावेशी बना रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में 'वन नेशन वन स्कॉलरशिप' की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में एडमिशन लेते ही, एक क्लिक के माध्यम से उनके एकाउंट में छात्रवृत्ति पहुंच सकेगी। प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति वितरण को तकनीक से जोड़ने का कार्य कर रही है। मनुष्य का हस्तक्षेप न्यूनतम करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस आधारित वेरीफिकेशन सिस्टम से जोड़ने का कार्य हो रहा है। विद्यार्थी और अभिभवक मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल टाइम छात्रवृत्ति ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा से जुड़ सकेंगे। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जनजागरुकता अभियान चलाते हुए पात्र और छूटे हुए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा से जोड़ा जाएगा। मेन्टरशिप व कैरियर गाइडेंस के माध्यम से छात्रवृत्ति को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। 'एक विद्यार्थी एक स्कॉलरशिप' की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा।छात्रवृत्ति योजना को आधुनिक तकनीक से जोड़कर सम्पूर्ण प्रणाली को आटोमेटेड करने से छात्र व संस्थानों को तकनीकी समस्यायें अत्यन्त न्यून हांगी। इसके लिए मोबाइल एप का विकास किया जा रहा है, जिससे छात्र आसानी से आवेदन पत्र को भर सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 01 करोड़ 23 लाख 13 हजार 201 छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम् तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के रुप में 9,150 करोड़ रुपये से अधिक की कुल धनराशि से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सामान्य वर्ग के कुल 58 लाख 90 हजार 280 छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम् तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति के रुप में 5,945 करोड़ रुपये से अधिक की कुल धनराशि से लाभान्वित किया गया है।अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग का कोई भी पात्र छात्र, छात्रवृत्ति से वंचित न रह सके, इसके दृष्टिगत वर्ष 2022-23 से समुचित बजट व्यवस्था की गयी है। जनपदीय समिति से स्वीकृत सभी पात्र छात्र-छात्राओं को धनराशि प्राप्त हो रही है।राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 की अवधि में अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 02 करोड़ 07 लाख 53 हजार 457 छात्र-छात्राओं को 13,535 करोड़ रुपये से अधिक की कुल धनराशि से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे महापुरुषों ने अपने पुरुषार्थ व परिश्रम के बल पर समाज को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर ने कोटि-कोटि वंचितों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ों का मार्गदर्शन किया। बाबा साहब द्वारा कही गईं बातें आज भी वंचितों व शोषितां को नई प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में सामर्थ्य व शक्ति है। विद्यार्थियां को प्लेटफार्म प्रदान करने का कार्य संस्थानों का होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों को सपोर्ट करने का काम सरकार का होना चाहिए। जब यह सभी मिलकर काम करेंगे, तो हम बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे। यही वर्ष 2047 का शताब्दी संकल्प है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्यार्थियों को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको जो स्कॉलरशिप व शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है, उसका उपयोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने हेतु करें।

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने में गांवों की सबसे अहम भूमिका : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 सितम्बर, 2025 को लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लगभग 57 हजार ग्राम प्रधानों व सदस्यों से संवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की परिकल्पना को साकार करने में गांवों की भूमिका सबसे अहम है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर होंगे, तो प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। जब प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रधानों को विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 के संकल्पों से परिचित कराते हुए इसे जन-जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों को विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 अभियान के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली एक वीडियो फ़िल्म भी दिखाई गई। क्यू0आर0 कोड तथा समर्थ पोर्टल के माध्यम से सुझाव देने के तरीके से भी अवगत कराया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत-2047 की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जब देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना हम सभी का साझा लक्ष्य है। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति में ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृतकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने 'पंच प्रण' लिए हैं। हर नागरिक इनको अपने जीवन में उतारे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि यदि गांव सशक्त होंगे तो भारत सशक्त होगा और यदि भारत सशक्त होगा तो वैश्विक मंच पर उसका नेतृत्व सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री जी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश सुशासन, बेहतर कानून-व्यवस्था, स्थिरता और शांति का पर्याय बन चुका है। विगत 08 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ रुपये से 35 लाख करोड़ रुपए हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 43 हजार रुपये से बढ़कर 01 लाख 20 हजार रुपये हो गई है। इन 08 वर्षों में 'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश' का निर्माण हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रधानों से आह्वान किया कि वे अपनी पंचायत की बैठकों में विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान पर चर्चा करें। गांव-गांव, वॉर्ड-वॉर्ड और मोहल्लों में लोगों को जोड़ें और समर्थ पोर्टल पर अधिक से अधिक सुझाव दिलाएँ। ग्राम प्रधानों को भेजे गए पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे पंचायत की खुली बैठक में जरूर पढ़ें। प्रत्येक जनपद के 03 और प्रदेश स्तर पर 05 सर्वोत्तम सुझावों को पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाली पीढियां आपके सुझावों पर गर्व करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रधानों से आह्वान किया कि वे अपनी पंचायत की बैठकों में विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान पर चर्चा करें। गांव-गांव, वॉर्ड-वॉर्ड और मोहल्लों में लोगों को जोड़ें और समर्थ पोर्टल पर अधिक से अधिक सुझाव दिलाएँ। ग्राम प्रधानों को भेजे गए पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे पंचायत की खुली बैठक में जरूर पढ़ें। प्रत्येक जनपद के 03 और प्रदेश स्तर पर 05 सर्वोत्तम सुझावों को पुरस्कृत किया जाएगा। आने वाली पीढियां आपके सुझावों पर गर्व करेगी।

उन्होंने ग्राम प्रधानों से आग्रह किया कि वे ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की राह पर आगे बढ़ें। विकसित भारत-2047 के स्वप्न को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गाँव अब सिर्फ बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि बदलाव की जीती-जागती मिसाल बन गए हैं।

विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 संवाद श्रृंखला में मुख्यमंत्री जी से हुए संवाद में ग्राम प्रधानों ने बताया कि विगत 08 वर्षों में जिस विकास को उन्होंने देखा, वह कभी सिर्फ एक सपना था। आज वही सपना हकीकत बनकर गाँव-गाँव में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर रहा है।

अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 सितम्बर, 2025 को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, ए0डी0जी0, आई0जी0, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही के साथ कुचल देगी। पर्व-त्योहारों के अवसर पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने के कुत्सित प्रयासों पर कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि 'दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है।' उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही समय है, सही समय है।

मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाल के दिनों में जनपद कानपुर नगर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महराजगंज, उन्नाव, सम्भल, आगरा और बरेली में आपत्तिजनक जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह घटनाएं प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए। आयोजकों और मास्टरमाइण्ड की पहचान कर उनकी सम्पत्ति तक की जांच हो। इन जुलूसों में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने पर्व एवं त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमाएं सुरक्षित सीमा से अधिक ऊंची न हों और नदियों में जलस्तर अधिक होने के कारण विसर्जन स्थल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुर्गा पूजा समितियों से संवाद कर विसर्जन व्यवस्था को सुरक्षित बनाएं और रावण दहन कार्यक्रम सुरक्षा मानकों के अनुरुप सम्पन्न कराएं। गो-तस्करी और बूचड़खानों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक औचक निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि बूचड़खाने मानक के अनुरुप ही संचालित हों।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे यू0पी0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो में भारी भीड़ है और विदेशी खरीदारों की मौजूदगी है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताहांत में सम्भावित बड़ी भीड़ को देखते हुए कहीं भी ट्रैफिक जाम न हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए।

मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयन्ती के अवसर पर इन दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए।

प्रदेश की 25 करोड़ जनता की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म तथा नैतिक दायित्व : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 सितम्बर, 2025 को यहां लखनऊ में द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विकसित उत्तर प्रदेश विजन-2047 कॉन्क्लेव का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी ने विगत 11 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। वर्ष 2014 में भारत दुनिया की 11वें नम्बर की अर्थव्यवस्था था। आज देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रुप में स्वयं को प्रस्तुत करेगा। यहां की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश चुप नहीं बैठ सकता। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की अपेक्षाएं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म तथा नैतिक दायित्व बनता है। इसी धर्म तथा दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रदेश सरकार विगत 08 वर्षों से अनवरत प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की आजादी के समय भारत की इकॉनमी में उत्तर प्रदेश का योगदान 14 प्रतिशत था। यह योगदान पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रदेश अपनी आबादी के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता हुआ दिखाई देना चाहिए। प्रदेश सरकार इसी कार्ययोजना के साथ कार्य कर रही है। यह हमारा राष्ट्रीय धर्म और दायित्व भी है।

पहले लोग प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी नहीं करते थे। आज देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में हैं। प्रदेश सबसे अधिक शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन कर रहा है। वर्ष 2017 से पूर्व यहां लखनऊ और वाराणसी स्थित एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील तथा गोरखपुर और आगरा में आंशिक रुप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट आती थी। आज 14 फ्लाइट्स देश के अलग-अलग शहरों को गोरखपुर से जोड़ रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट्स क्रियाशील हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शीघ्र ही लोकार्पित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट तथा एयर कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर एक पर है। यहां देश की पहली रैपिड रेल तथा पहला इनलैण्ड वॉटर-वे मौजूद है। प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 का सबसे बड़ा बेस है। उत्तर प्रदेश गन्ना, चीनी, इथेनॉल तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में नम्बर एक पर है। यह सबसे बड़ी युवा आबादी का राज्य होने के साथ-साथ सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य बन चुका है। प्रदेश की अभूतपूर्व विकास यात्रा को देश और दुनिया देख रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य की विधानसभा में उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेन्ट 2047 पर 24 घण्टे अनवरत चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने सत्र के दौरान अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। वर्तमान में इस विषय पर निचले स्तर पर डिबेट चल रही है। 300 से अधिक इंटेलेक्चुअल फील्ड में भेजे गए हैं। उन्होंने अब तक 110 से अधिक विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों को कवर किया है। वह अलग-अलग तबके के लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। संगोष्ठियां हो रही हैं। समर्थ यू0पी0 पोर्टल के माध्यम से आमजन के सुझावों को प्राप्त करना प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश के अलग-अलग कोने से अब तक लगभग 06 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 52वें निजी विश्वविद्यालय को अपनी अनुमति दी है। प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। यह पॉलिसी सबके लिए समान है। इसमें पिक और चूज की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदेश सरकार ने सहारनपुर में मां शाकुम्भरी, मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी, मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी तथा आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज की अवधारणा पर कार्य करते हुए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीनी धरातल पर उतारा जा चुका है। 05 लाख करोड़ रुपये का निवेश ग्राउण्ड ब्रेकिंग के लिए तैयार है। प्रदेश में 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयां दो करोड़ लोगों को रोजगार दे रहीं हैं। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में देश के 55 प्रतिशत मोबाइल फोन बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट के निर्माण में प्रदेश 55 प्रतिशत से अधिक योगदान दे रहा है। राज्य विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है।

भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत उतना मजबूत और लोक कल्याण एवं वैश्विक कल्याण उतना ही सशक्त होगा : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 सितम्बर, 2025 को जनपद श्रावस्ती में 510 करोड़ रुपये लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 233 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 276 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्मिलित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के 01 व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के 02 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति चेक तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के 05 लाभार्थी परिवारों को 05-05 लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नये भारत का दर्शन हो रहा है। विकास और विरासत की एक नई आभा देश में देखने को मिल रही है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सबसे सुन्दरतम नगरी के रुप में स्थापित हो रही है। इस बार पुनः दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति जितनी समृद्ध होगी, भारत उतना मजबूत होगा। लोक कल्याण एवं वैश्विक कल्याण उतना ही सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जनपद श्रावस्ती में माता जानकी के वन के समय की इस पावन धरा और त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रावस्ती जनपद का महत्व पौराणिक काल से रहा है। भगवान श्री राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती में राजधानी बसायी थी। जनपद श्रावस्ती भगवान बुद्ध की धरती है। यही वह स्थान है, जहां तथागत बुद्ध ने 24 चातुर्मास व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध की साधना से श्रावस्ती की धरती पवित्र हुई है। यह जैन धर्म के तीर्थंकरों की साधना और सिद्धि की धरा रही है। भगवान सम्भवनाथ जी इसी पावन धरा पर अवतरित हुए थे। महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का कार्य भी इसी धरती से किया था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज से 2000 वर्ष पूर्व महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य के समय श्रावस्ती भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। पाटलीपुत्र से तक्षशिला तक जाने वाला उत्तरपथ का महत्वपूर्ण केन्द्र श्रावस्ती हुआ करता था। ऐसे पौराणिक, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद में आना अत्यन्त सौभाग्यशाली है। यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद श्रावस्ती के लिए स्वीकृत 510 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास सम्पन्न हो रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने 07 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयन्ती पर प्रदेश में अवकाश की घोषणा करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयन्ती 07 अक्टूबर को पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक देव मन्दिर में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का अखण्ड पाठ कराया जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद श्रावस्ती ने विकास के प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने यहां हो रहे विकास कार्यों को आज माता सीताद्वार मंदिर एवं महर्षि वाल्मीकि के पावन आश्रम में आकर देखा है। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था के प्रतीक हैं। संस्कृत का पहला मौलिक ग्रन्थ एवं दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने हम सभी को प्रदान किया है। यह ग्रन्थ हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है

विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित श्रावस्ती आज की आवश्यकता है। यहां लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई परियोजनाएं शिक्षा, उच्च शिक्षा, सड़क, पशुधन एवं जीवन के विभिन्न आयामों से सम्बन्धित हैं। जनपद श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट के माध्यम से यहां देश और दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, जिससे जनपद श्रावस्ती विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विरासत का सम्मान करेगी, विकास करेगी और आपकी सुरक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश एक नये अभियान के साथ आगे बढ़ा है। आगामी 22 वर्षों में हमें कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए, उस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश हेतु 12 सेक्टर तय किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, रोजगार, कौशल मिशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवेश, शहरीकरण, पर्यटन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी को लेकर विकसित उत्तर प्रदेश अभियान को आगे बढ़ाया गया है। इससे सम्बन्धित साहित्य सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया गया है।

आदिवासी समाज हमारी गौरवशाली ऋषि परम्परा का वाहक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 सितम्बर, 2025 को यहां 17वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ भ्रमण पर आए मध्य प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया।

जनजातीय समाज के युवाओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान की धरोहर जंगलों में ही रची गयी है। इस प्रकार आदिवासी समाज हमारी गौरवशाली ऋषि परम्परा का वाहक है। उन्होंने कहा कि जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को अलग-अलग राज्यों की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' संकल्प का अच्छा उदाहरण है। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के लिए आदिवासी युवाओं व अन्य सभी समाजों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। जनजातीय समाज के लोगों को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़कर देश को आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छी चीजों को जीवन में अंगीकार करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है तथा नकारात्मक दृष्टि विघटन व विनाश का कारण बनती है। विकास की सकारात्मक सोच को हमें आगे बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। आदिवासी युवाओं द्वारा देश के लिए दिया गया योगदान अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत की प्रथम नागरिक जनजातीय समुदाय से ही आती हैं। ऐसा इसलिए सम्भव हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और कभी हार नहीं मानी। हमें मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारी भाषा भले ही अलग-अलग हो लेकिन भाव एक ही है।

बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संविधान के आधार पर देश का कानून चलता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा का भी यह 150वाँ जयन्ती वर्ष है, जिन्होंने समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया तथा जनजातीय समाज को संगठित कर भारत की धरती से विदेशी हुकूमत को भागने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। वनवास के दौरान वह जनजातीय समाज के सबसे बड़े मित्र बने। अयोध्या से श्रीलंका जाते समय वे अपने साथ सेना नहीं ले गए थे, बल्कि जनजातीय लोगों के साथ मित्रता की और आगे के अभियान में उनका सहयोग प्राप्त किया। आज भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मन्दिर का निर्माण हो गया है। आज अयोध्या काफी विकसित हो गया है। हमें अयोध्या और लखनऊ को विकास का मॉडल बनाना चाहिए।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास व सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा के बिना विकास सम्भव नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए विकास आवश्यक है तथा विकास के लिए सुरक्षा आवश्यक है। जनजातीय समाज के जागरूक युवा विकास के एजेण्डे को लोगों के एजेण्डे के साथ जोड़कर इस विकास कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें विकास से नहीं भटकना है। विकास को गति देने के लिए प्रदेश में स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी। जनजातीय क्षेत्रों में भी इस कार्य को आगे आगे बढ़ाना है।

आज उत्तर प्रदेश आई0टी0, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑर्टिफिशियल इण्टेलिजेन्स का बहुत बड़ा केन्द्र बन चुका है। हमें आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए, जो कि विकसित भारत का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। विकसित भारत 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का भारत होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष विकसित भारत का विजन रखा है। प्रदेश के सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिला है व उनकी आय में वृद्धि हुई है। जब जिले विकसित होंगे, तो प्रदेश व देश भी विकसित होगा। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण को अंगीकार कर साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए तथा गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना चाहिए। हमें सकारात्मक भाव से आगे बढ़ना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों व देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को साकार करता है। हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश के तीन जिले मिर्जापुर, सोनभद्र व चन्दौली नक्सल प्रभावित थे। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में कोई भी नक्सल प्रभावित जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जहां सभी आदिवासी परिवारों का सरकारी योजनाओं से पूर्ण संतृप्तीकरण हो चुका है। प्रत्येक आदिवासी परिवार के पास जमीन, मकान, पेयजल, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व रोजगार आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी जगह खुशहाली है और आदिवासी समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विजयदशमी के अवसर पर जन-जन की आस्था से जुड़ते हुए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को अनुमोदित कर दिया है। कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 69 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

- मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) क्रय नीति को अनुमोदित कर दिया है। वर्ष 2025-26 हेतु मोटे अनाजों के अन्तर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति कुन्तल, बाजरा का 2,775 रुपये प्रति कुन्तल, ज्वार (हाईब्रिड) का 3,699 रुपये प्रति कुन्तल एवं ज्वार (मालदाण्डी) का 3,749 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलेण्डर रिफिल वितरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आच्छादित लाभार्थियों का जीवन-यापन सुविधाजनक होगा।

- मंत्रिपरिषद ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे तक लिंक एक्सप्रेस-वे वाया फर्रुखाबाद हेतु प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण इन्जीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एवं कन्स्ट्रक्शन (ई0पी0सी0) पद्धति पर 06 लेन (08-लेन विस्तारणीय) चौड़ाई में किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एक्सप्रेस-वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (चैनेज 133+800), कुदरैल (इटावा) से प्रारम्भ होकर गंगा एक्सप्रेस-वे के चैनेज 282+845, सवाइजपुर (हरदोई) पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस-वे की प्रस्तावित लम्बाई 90+838 कि0मी0 एवं लागत 7488.74 करोड़ रुपये है।

- मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण को धनराशि स्वीकृत करने एवं व्यय के प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित कर दिया है।

- मंत्रिपरिषद ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने तथा बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- मंत्रिपरिषद ने संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों को अनुमोदित कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख स्थानों पर एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किए जाएंगे।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत मेसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकण्डक्टर परियोजना की स्थापना हेतु निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट संशोधित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में सेमीकण्डक्टर इकाई की स्थापना होगी। इससे भारत सेमीकण्डक्टर उत्पादों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। प्रस्तावित परियोजना से 780 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष तथा लगभग 3,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष, इस प्रकार लगभग 3,780 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होगा।

- मंत्रिपरिषद ने निजी क्षेत्र के अन्तर्गत राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, चन्दौसी, सम्भल, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 की धारा-7, उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम के संशोधन के माध्यम से उप धारा (3) में वर्णित अनुसूची-2 में उल्लिखित अन्तिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 में संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश-2025 को प्रख्यापित किए जाने तथा उसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख्य पर उच्च शिक्षा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित/पारित कराए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मंत्रिपरिषद ने उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में गांधी विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था संत माँ कर्मा मानव संवर्धन ट्रस्ट, झांसी को शर्त के अधीन आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी के अन्तर्गत ग्राम अम्बाबाय एवं ग्राम रुद्र करौरी, तहसील व जनपद झांसी में 20.21 एकड़ भूमि में प्रस्तावित है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अन्तर्गत ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की प्रायोजक संस्था एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली-2021 के परिशिष्ट-6 के प्रारुप पर शपथ पत्र, अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली-2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
  ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 प्रख्यापित है, जिसमें अब तक 13 संशोधन हो चुके हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-6003/2021 प्रेमलता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुपालन में चौदहवाँ संशोधन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025' के प्रख्यापन के पश्चात इस नियमावली के नियम-5 (1) में निम्नवत परन्तुक जोड़ा जा रहा हैः-
  'परन्तु यह और भी कि मृत सरकारी सेवक जिस समूह में मृत्यु के समय कार्यरत था, मृत सरकारी सेवक के आश्रित को उस समूह से उच्चतर समूह में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  परन्तु यह और कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित को केवल समूह 'ग' के पद (ऐसी सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के भीतर आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के भीतर थे और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि के भीतर रख दिया गया है) और समूह 'घ' के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।'

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित